5 फरवरी 2020

'मातृ वंदना' के सफल क्रियान्वयन के लिए हरियाणा को तीन अवार्ड

चंडीगढ़, 4 फरवरी (ट्रिब्यू)

हरियाणा को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने तीन पदकों से नवाजा है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने मंगलवार को यहां कहा कि गत दिवँस नयी दिल्ली में हुए समारोह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्य को ये पुरस्कार दिए। हरियाणा को यह पुरस्कार सितंबर-2017 से दिसंबर-2019 तक की अवधि में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया है।

■ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया सम्मानित

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा यह योजना जनवरी-2017 से देश के सभी जिलों में शुरू की गई थी। योजना के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में खर्च का वहन किया जा रहा है। राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब तक 159 करोड़ 91 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। योजना के तहत जनवरी-2017 से 28 जनवरी, 2020 तक 3 लाख 70 हजार 646 लाभानुभोगियों ने अपना पंजीकरण करवाया है।

जनवरी-2017 में योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 3,55,739 लाभानुभोगियों को 152.72 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।.योजना के तहत गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर को सुधारने और इस दौरान माताओं को होने वाले वेज लॉस की आंशिक भरपाई के लिए तीन किश्तों में 5,000 रुपये की राशि अदा की जाती है।

दैनिक दिव्य
५ फरवरी २०२०

सरकार का फैसला

प्रदेश की 26 हजार आंगनबाड़ी वर्करों को मिलेंगे स्मार्टफोन

सुरेंद्र सिंह सांगवान/ट्रिब्यून
पंचकूला, 3 फरवरी

समेकित बाल विकास परियोजना के तहत कार्यरत हरियाणा की करीब 26 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। इसके अलावा मार्च के अंत तक आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों के खाली पदों को भी भरा जाएगा। विभाग बीपीएल की महिलाओं को सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराने के लिये 40 करोड़ की राशि खर्च करने जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक मनोज कुमार के अनसार 28 करोड़ रुपए की लागत से 28 हजार मोबाइल फोन विभाग की ओर से खरीदे जाएंगे। ये मोबाइल फोन आंगनबाड़ी वर्करों और सुपरवाइजरों को उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्करों को स्मार्ट फोन देने से उनसे तुरंत ऑनलाइन जानकारी मांगी जा सकती है और उन्हीं दी जा सकती है। इस समय प्रदेश में 26 हजार 962 आंगनबाड़ी वर्कर हैं। उन्होंने बताया कि वर्कर्स के माध्यम से बीपीएल की महिलाओं को सेनेटरी नेपकिन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इनकी खरीद पर 40 करोड़ की राशि खर्च होगी। इस कार्य के लिये टेंडर हो चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हेल्पर्स के 1047 और वर्कर्स के 860 और सुपरवाइजरों के करीब 200 पदों को जल्द भरा जाएगा। वर्कर्स व हेल्पर्स के पद जल्द भरने के लिये उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्तों को एक-दो दिन में पत्र भेज दिया जाएगा। सुपरवाइजरों के पद भरने के लिये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को लिखा जा चुका है।

जिला	वर्कर	हेल्पर
अम्बाला	23	48
भिवानी	20	27
फरीदाबाद	06	31
फतेहाबाद	29	47
गुरुग्राम	28	47
हिसार	19	56
जींद	29	100
झज्जर	40	18
कैथल	23	46
कुरुक्षेत्र	11	8
करनाल	11	11
मेवात	70	83
नारनौल	34	72
पंचकूला	18	41
पानीपत	6	08
पलवल	47	99
रोहतक	10	30
रेवाड़ी	30	47
सिरसा	331	101
सोनीपत	53	86
यमुनानगर	22	41

दैनिक ट्रिब्यून

2 फरवरी 2020

मंत्रालय को पिछले बजट से 14 फीसदी ज्यादा

महिलाओं और बच्चों के कल्याण को 30 हजार करोड़

नयी दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसी)

लोकसभा में शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आवंटित राशि से 14 फीसदी अधिक है। पोषण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण समेत सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए भी बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 के 3891.71 करोड़ रुपये की अपेक्षा 2020-21 में इसके लिए 4036.49 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भी मौजूदा वित्त वर्ष के 3400 करोड़ रुपये की अपेक्षा आगामी वित्त वर्ष के लिए 3700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 'वन स्टॉप सेंटर' योजना के लिए भी बजटीय आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और मौजूदा वित्त वर्ष के 204 करोड़ रुपये की अपेक्षा आगामी वित्त वर्ष के लिए 385 करोड़ का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए बजटीय आवंटन 2300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिला को उसके बच्चे के जन्म पर 6 हजार रुपये दिये जाते हैं। बाल सुरक्षा सेवा के लिए बजट का आवंटन 1350 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया गया है। इस प्रकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजटीय आवंटन में मौजूदा वित्त वर्ष की अपेक्षा 14 फीसदी वृद्धि के साथ आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल मिला कर 30,007.10 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के लिए 220 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। महिला शक्ति केंद्र के लिए बजटीय आवंटन दो गुना कर इसे 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल 29 हजार 720.38 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है जो पिछले साल की अपेक्षा 3804 करोड़ रुपया अधिक है।

दैनिक ट्रिब्यून

23 जनवरी, 2020

कन्या भ्रूणहत्या रोकने के लिए कार्यक्रम

मोरनी (निस) : महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालिका दिवस सप्ताह के तहत खंड मोरनी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बेटी सम्मान और महिलाओं के विकास के प्रति जागरूक करने का प्रयास करना तथा कन्या भ्रूणहत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने सुंदर सुंदर स्लोगन लिखे। जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर तनुश्री ने स्लोगन का निरीक्षण किया और प्रथम, द्वितीय व तृतीया स्थान के छात्रों का आंकलन किया। जिसमें प्रथम स्थान नौंवी कक्षा की नीलाक्षी ने, दूसरे स्थान पर इसी कक्षा की हिमानी ने तथा तीसरा स्थान योगिता ने प्राप्त किया।